Need for repatriation of Tamil andTelgu youths stranded in Malaysia

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Ten youths from Tamil Nadu and six from Andhra Pradesh had gone to Malaysia on valid work permits, but were cheated by the agency. They have not been provided employment in the places indicated in their visa papers and work permits. These youths are in a state of acute distress with no employment, no salary and not even the wherewithal to fund or tind their meals. The youths approached the Indian High Commission in Malaysia, but their grievances were not addressed. This is a growing concern and it is high time for the Ministry of External Affairs to evolve a mechaism to screen and check *bona fides* of travel agencies. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has already written a letter to the Prime Minister and the External Affairs Minister requesting them to ask the Indian High Commission in Kuala Lumpur to take up the matter immediately with the Government of Malaysia to provide relief to these youths and repatriate them to India expeditiously. Therefore, I humbly request the Union Government to provide the stranded Tamil and Telgu youth immediate relief and render justice to them.

Need for finding permanent solution to problem of drought in the country

श्री पी.के.माहेश्वरी (मध्य प्रदेश)**:** उपसभापति महोदया, पिछले कई सालों से देश सूखे की स्थिति से जूझ रहा हैं। इस वर्ष देश के अधिकाशं भागों में अच्छी बारिश के बावजूद कई राज्यों में सूखे की स्थिति बनी हुई हैं। इस समस्या का निदान बहुत जरूरी है अन्यथा विकास की गति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। केन्द्र सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए उसे संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम गठित करनी चाहिए , जो गहराई तक जा कर इस समस्या का अध्ययन करे और उपाय ढूंढे। हालांकि यह समस्या एक दो सालों में हल नहीं होगी, लेकिन यदि सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों पर दीर्घकालीन उपायों को लागू करे तो कुछ सालों बाद सुखद परिणाम सामने आ सकते हैं। इस वर्ष अच्छी बारिश के बावजूद महाराष्ट्र एंव अन्य कुछ राज्य सूखे से जूझ रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यक्रम तात्कालिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधन नहीं कर सकते हैं। यह बात भी हर बार देखने में आती है कि सभी लोगों के पास राहत नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए जरूरी हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को तत्काल विशेषज्ञों की टीम गठित कर दीर्घकालीन रणनीति बनाने के काम में जुट जाना 259